

जनहित , माध्यम और सूचना समाज

डॉ.शशि रानी, एसोसिएट प्रोफेसर

डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

सार

पत्रकार अपने काम के लिए सबसे आम औचित्य यह बताते हैं कि यह "जनहित में" है। यही वह धारणा है जो सत्ता में बैठे लोगों से कठिन प्रश्न पूछने, दूसरों की निजता पर आक्रमण करने और कभी-कभी सत्य की खोज के लिए नैतिक अभ्यास की सीमाओं का परीक्षण करने के लिए पत्रकारिता के नैतिक अधिकार को रेखांकित करती है। जनहित केवल वही नहीं है जो पाठक, श्रोता या दर्शक या तो उपभोक्ता के रूप में चाहते हैं या ऐसे लोग जो मनोरंजन करना चाहते हैं, यह उन मुद्दों के बारे में है जो सभी को प्रभावित करते हैं, भले ही उनमें से बहुतों को इसके बारे में पता न हो या भले ही वे परवाह न करते हों।

आम तौर पर, पत्रकारों और संपादकों के लिए यह स्पष्ट है कि जनहित में क्या है और क्या नहीं है, लेकिन कभी-कभी यह एक जटिल प्रश्न बन जाता है, विशेषकर जहां गोपनीयता का संबंध है।

1. परिचय

हाल के वर्षों में मीडिया और संचार नीति के क्षेत्र में मुद्दों के बारे में - और चिंता के बारे में नागरिक जागरूकता में नाटकीय वृद्धि देखी गई है। स्वामित्व नियमन से लेकर संचार प्रौद्योगिकियों, सामुदायिक मीडिया के विकास तक के मुद्दे अब नीति निर्माण क्षेत्र से बहुत आगे निकल गए हैं। कई पर्यवेक्षकों ने इस घटना को इन क्षेत्रों में जनहित संगठन की सक्रियता के विकास के साथ जोड़ा है - विकास जो इस तरह से हुआ है और जिसका ऐसा प्रभाव है कि क्षेत्र को तेजी से एक वैध सामाजिक

आंदोलन के रूप में चित्रित किया जा रहा है (पार्कर., और अन्य 2012)। अन्य ने हाल के वर्षों में संचार नीति क्षेत्र में नीति-निर्माण गतिविधि में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है, जो नागरिक हित और सार्वजनिक हित गतिविधि को प्रतिबिंबित और प्रोत्साहित कर सकती है। मीडिया की संचार नीति क्षेत्र में सक्रियता और वकालत कार्य की बढ़ती गतिविधि छात्रवृत्ति की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जो इन गतिविधियों की जांच करती है, उन्हें व्यापक ऐतिहासिक और सैद्धांतिक संदर्भों में रखती है, और जो संगठनों की संरचना की खोज करती है।

2. विषय विस्तार

सिहोन, (2017) का मत है, कुछ आकलनों के अनुसार, जनहित मीडिया वकालत और सक्रियता पर ज्ञान की स्थिति का अभाव रहा है, जबकि सामाजिक आंदोलनों पर साहित्य ने सक्रियता को सक्षम करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका पर पर्याप्त ध्यान दिया है, "इस साहित्य में से लगभग कोई भी नहीं देखता है सक्रियता के उद्देश्य के रूप में संचार और सूचना नीति"। इस तरह के लक्षण कई संभावित कारणों से मामले को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं (जैसा कि यह समीक्षा स्पष्ट करेगी)। पहला कारण इन लेखकों का साहित्य पर ध्यान केंद्रित करना हो सकता है जो विशेष रूप से सामाजिक आंदोलन सिद्धांत के माध्यम से इस आंदोलन की जांच करता है। इस क्षेत्र के लिए इस विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का आवेदन अपेक्षाकृत हाल की घटना है, पहले के विश्लेषण अक्सर नियामक निर्णय लेने या नीति निर्माण प्रक्रिया के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, या मुख्य रूप से ऐतिहासिक कथाओं में एक विशेष सैद्धांतिक कमी होती है।

जनहित मीडिया को यहां मीडिया के रूप में परिभाषित किया गया है जो स्वतंत्र है, जो लोगों को उनके जीवन को आकार देने वाले मुद्दों पर सूचित करने के लिए मौजूद है, जो सार्वजनिक बहस और संवाद को सक्षम करने के लिए किसी भी राजनीतिक, वाणिज्यिक या गुटिय हित के

बजाय जनता की सेवा करते हैं। पूरे समाज में, और सत्ता में बैठे लोगों को जनहित की ओर से जवाबदेह ठहराने के लिए कार्यरत है। इसका मतलब है कि समाज भर में सभी लोगों के हितों में काम करने वाले नैतिक और विश्वसनीय मीडिया पर ध्यान केंद्रित करना, न कि केवल उन लोगों के लिए जिनके पास भुगतान करने की शक्ति या पैसा है - या प्रभाव - मीडिया। इस तरह के एक फंड का दायरा वाणिज्यिक, समुदाय, सार्वजनिक सेवा और नागरिक मीडिया सहित एक सूचित और लगे हुए समाज का समर्थन करने वाले मीडिया संस्थानों की पूरी श्रृंखला को शामिल करेगा।

ट्रैपेल, (2018), के अनुसार आंदोलन कई रूपों में और लेबल की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संचालित हुआ है, खासकर जब विश्लेषण का दायरा प्रकृति में वैश्विक है। और जबकि यह मामला है कि आंदोलन के भीतर (या इसके संबद्ध क्षेत्रों में से एक) के पास एक विशेष शब्दावली के दूसरे पर पालन करने के लिए निर्विवाद रूप से वैध और सम्मोहक कारण हैं (यानी, मीडिया सुधार बनाम मीडिया न्याय, बनाम मीडिया लोकतंत्र, बनाम संचार अधिकार, आदि), साहित्य की इस समीक्षा ने इस क्षेत्र में संचित ज्ञान को व्यापक-रूप से विकसित करने के लक्ष्य के साथ एक व्यापक जाल बिछाया है। यह दृष्टिकोण अन्य अध्ययनों को दर्शाता है, जिन्होंने आंदोलन के सभी प्रासंगिक उप-घटकों (जैसे, मीडिया सुधार, मीडिया न्याय, मीडिया लोकतंत्र) को एक विश्लेषणात्मक फ्रेम में शामिल किया है। परिणामतः यह समीक्षा केवल मीडिया सुधार आंदोलन बनाम मीडिया न्याय आंदोलन या संचार अधिकार आंदोलन के विभिन्न रूपों को ब्यक्त करने से संबंधित है। प्राथमिकताओं का यह समूह इस धारणा को दर्शाता है कि इन विभिन्न आंदोलन क्षेत्रों के भीतर भी संभवतः यह स्वीकार करेंगे कि मीडिया और संचार प्रणाली के सुधार के लिए आंदोलन, चाहे इसे कैसे भी परिभाषित किया गया हो, इसका एक एकीकृत संपूर्ण के रूप में उपयोगी रूप से अध्ययन किया जा सकता है।

अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के प्रारंभिक निर्माण मीडिया नीतियों और विनियमों के आसपास के समकालीन मुद्दों को समझने की अनुमति देते हैं। यह स्वतंत्रता व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकारों से संबंधित है (वैन डेन ब्लक., एट अल 2018)। इसकी शुरुआत में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लेखक के प्रकार पर केंद्रित थी और इस प्रकार व्यक्तिगत अधिकारों (जो सार्वजनिक हित को प्रतिबंधित करती है) की तुलना में सार्वजनिक हित की परिभाषा के दायरे पर केंद्रित थी।

भविष्य के किसी भी नियामक समझौते में सार्वजनिक हित को सुरक्षित करने के लिए, जनता की आवाज को स्वीकार करने की आवश्यकता है, और इस बात को अधिक मान्यता दी जानी चाहिए कि जनता को यह निर्धारित करने में शामिल किया जा सकता है कि सार्वजनिक हित में क्या है। उन विकल्पों में से जो इसे प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

जनहित के संबंध में मीडिया की गोपनीयता के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- **पारदर्शिता:** जहां कहीं भी ऐसा करना संभव हो, गोपनीय स्रोतों को खतरे में डाले बिना, समाचार पत्रों (मीडिया)को इस बारे में अधिक खुला होना चाहिए कि किस प्रकार कहानियों में निहित जानकारी हासिल की गई है, जिससे उपभोक्ताओं (पाठकों/दर्शकों) को अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

- **शासन:** समाचार पत्रों को अपने कार्य के स्वरूप के अनुसार पाठकों को औपचारिक प्रतिनिधित्व देने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अधिक समाचार पत्र पाठकों के संपादकों को नियुक्त कर सकते हैं और शिकायतों और नैतिकता के मामलों पर विचार करने के लिए नियमित स्थान दे सकते हैं।

• **हिमायत:** नए प्रेस नियामक को अपने ढांचे के भीतर जनता की आवाज को बढ़ाने के तरीके खोजने चाहिए। एक विकल्प यह होगा कि अन्य नियामकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपभोक्ता वकालत मॉडल से सीखें - और एक सार्वजनिक पैनल बनाएं जो सालाना आधार पर प्रेस शिकायत आयोग (पीसीसी) के उत्तराधिकारी का जनहित ऑडिट प्रदान कर सके।

आत्मज्ञान के विचारकों के साथ अठारहवीं शताब्दी के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की समझ बदल गई। उन्होंने नए राजनीतिक विचारों को फैलाने और शासी शक्तियों की आलोचना करने वाले उदार विचारों को संप्रेषित करने के लिए "सीखने वाले समाजों, पत्रिकाओं और प्रकाशनों की बाढ़" का इस्तेमाल किया (फोस्टर., और अन्य 2018)। मुद्रित समाचार पत्रों की अधिक संख्या राजनीतिक कार्रवाइयों का एक महत्वपूर्ण चालक थी। उदाहरण के लिए, प्रिंटिंग प्रेस ने 1848 की फ्रांसीसी क्रांति होने में मदद की।

प्रबुद्ध विचारकों ने जल्दी ही समझ लिया कि प्रेस की स्वतंत्रता राजनीतिक बहस और संभावित राजनीतिक परिवर्तन सुनिश्चित करेगी। प्रेस की स्वतंत्रता को पहली बार 1766, स्वीडन में रॉयल ऑर्डिनेंस फॉर फ्रीडम ऑफ राइटिंग एंड पब्लिशिंग द्वारा प्रख्यापित किया गया था। यह केवल आठ वर्षों तक ही रहा, लेकिन इसने भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

आमतौर पर, व्हिसलब्लोअर(मुखबिर) और प्रेस के सदस्यों दोनों को जनहित के सेवक के रूप में देखा जाता है (और खुद को देखें)। पूर्व के बारे में, राजनीतिक दार्शनिक, कानूनी विद्वान व्हिसलब्लोअर संरक्षण कानून, और अदालतें सभी इस बात से सहमत हैं कि एक व्हिसलब्लोअर द्वारा वर्गीकृत दस्तावेजों का खुलासा करके राज्य की गोपनीयता का उल्लंघन उचित है यदि यह सार्वजनिक हित में कार्य करता है। इसी तरह, समाचार मीडिया को जनहित का प्रहरी माना जाता है; वे सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए दावों पर सवाल उठाकर, इस प्रकार उन्हें ध्यान में रखते हुए, और नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी

प्रदान करके सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा, जब पत्रकार ऐसे तरीके अपनाते हैं जो पहली नज़र में अनैतिक लगते हैं - जैसे कि प्रेस में अवैध रूप से लीक की गई जानकारी के आधार पर एक कहानी प्रकाशित करना - तो वे अपने कार्यों को सार्वजनिक हित के लिए अपील करके अपने कार्यों को सही ठहरा सकते हैं।

जनहित के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं:

सामूहिक सिद्धांत-

सामूहिक सिद्धांत के अनुसार, जनहित में केवल कई सदस्यों के हितों का योग होता है जो इसे बनाते हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष कानून या नीति सार्वजनिक हित में है, हमें जनता के प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य के कल्याण पर इसके प्रभावों का निर्धारण करना चाहिए और परिणामों का मिलान करना चाहिए।

प्रक्रियात्मक सिद्धांत-

प्रक्रियात्मक सिद्धांत का तर्क है कि एक विचारशील लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो भी परिणाम होता है वह जनहित में होता है (कोसेवा., और अन्य 2018)। हालांकि विचार-विमर्श करने वाले अभी भी अपने निजी हितों के साथ शुरू करते हैं, आशा है कि विचार-विमर्श की प्रक्रिया - जिसमें अन्य बातों के अलावा, किसी की स्थिति के लिए कारण देना पड़ता है जिसे अन्य स्वीकार्य मान सकते हैं - उन निजी हितों को बदल देगा ताकि अंतिम विचार-विमर्श का परिणाम (कानून या नीति पर निर्णय लिया गया) जनहित में होगा। इस प्रकार प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण लोकतांत्रिक विचार-विमर्श के माध्यम से सार्वजनिक हितों को निजी हितों की अपेक्षा अधिक महत्व दिए जाने की धारणा पर आधारित है।

एकात्मक सिद्धांत-

व्यक्तिवाद की समस्या से बचने के लिए एकात्मक सिद्धांत विकसित हुआ। यह सिद्धांत सार्वजनिक हित को लोगों के निजी हितों से नहीं, बल्कि एक व्यापक नैतिक सिद्धांत से प्राप्त करता है जो निजी और सार्वजनिक हितों पर समान रूप से लागू होता है (जस्टेल., और अन्य 2018)। इसका मानना है, एक कानून या नीति सार्वजनिक हित में नहीं हो सकती है यदि वह सभी के हित में नहीं है, और यह वास्तव में व्यक्तियों के हित में नहीं हो सकता है यदि यह सार्वजनिक हित में नहीं है।

नागरिक सिद्धांत-

जनहित के सिद्धांतों की यह संक्षिप्त चर्चा जनहित के लिए निम्नलिखित वांछनीयता उत्पन्न करती है:

1. इसे परस्पर विरोधी हितों की अनुमति देनी चाहिए।
2. यह निजी, व्यक्तिगत हितों से शुरू नहीं हो सकता।
3. यह एक व्यापक सिद्धांत से जनहित प्राप्त नहीं कर सकता है ।

3. निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो रहा है कि मीडिया को विशेष रूप से जनहित के क्षेत्र में तटस्थ और वास्तविक समाचार प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। यह संविधान में व्यक्त उच्च-स्तरीय हितों के प्रति प्रेस की प्रतिक्रिया होगी, जो समाज में व्यक्तियों और समूहों के हितों से संबंधित है। संचारक(मीडिया) और प्रापक(उपभोक्ता/पाठक दर्शक/श्रोता) के बीच यह परस्पर क्रिया समाज को संप्रेषित किए जाने वाले उपयुक्त संदेशों का निर्धारण करेगी और उम्मीद है कि उन संदेशों की जनहित सामग्री को ठोस बनाएगी। इस तरह की एक परिचालन प्रणाली की निगरानी

से जनहित / प्रेस हित की एक प्रणाली को परिचर सिद्धांत और कार्यप्रणाली के साथ तैयार किया जाएगा। तभी किसी वैधता और निश्चितता के साथ जनहित का निर्धारण किया जा सकेगा। ।

वास्तव में परिप्रेक्ष्य में अंतर के कारण जनहित एक फिसलन भरा विषय है क्योंकि सामान्य आधार खोजना अक्सर मुश्किल होता है। प्रत्युत आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भौतिक और सामाजिक प्रौद्योगिकी में नवाचारों को तैयार किया जाना चाहिए। यही समाज के कल्याण का आधार है। अन्य सार्वजनिक हित सुशासन से संबंधित हैं। प्रौद्योगिकी के विकास से पत्रकारिता की प्रकृति निरंतर बदल रही है, लेकिन पेशा अभी भी मुख्य रूप से "कहानियों को बेचने" के बारे में है। मीडिया उत्पादों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो लोगों में और जिनमें लोग रुचि रखते हैं। यह असंभव है कि सफल नवप्रवर्तन पत्रकारिता उस रास्ते से बहुत कुछ भटक सकती है। जनहित कमोबेश वही रहता है। जनहित ही वह सशक्त आधार है, जो मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है।

4. संदर्भ

सिहोन, पी।, शूएट, जे।, और बॉम, एस। डी। (2017)। जनहित में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉरपोरेट गवर्नेंस। सूचना, 12(7), 275.

और ट्रैपेल, जे। (2018)। मीडिया एकाग्रता और जनहित। मीडिया नीति। अभिसरण, एकाग्रता और वाणिज्य, 38-59।

ज़ांग, जे। (2011)। जनहित प्रौद्योगिकी में केस स्टडीज (डॉक्टरेट शोध प्रबंध, हार्वर्ड विश्वविद्यालय)।

वेंग, जे। (2015)। लोग महामारी के दौरान क्या खोज रहे हैं? GOOGLE खोजों के माध्यम से सार्वजनिक हित के निर्धारकों की खोज करना।

हजरवर्ड, एस। (2018)। सोशल नेटवर्क मीडिया के युग में सार्वजनिक सेवा।

वैन डेन बल्क, एच।, डॉंडर्स, के।, और लोव, जीएफ (2018)। नेटवर्क वाले समाज में सार्वजनिक सेवा मीडिया: कौन सा समाज? कौन सा नेटवर्क? क्या भूमिका?।

फोस्टर, एस। (2018)। मीडिया की जिम्मेदारी, जनहित में प्रसारण, और रिचर्ड बनाम बीबीसी में निर्णय। यूरोपीय मानवाधिकार कानून की समीक्षा, (5), 490-505।

पार्कर, ए जे (2012)। तंत्रिका विज्ञान और सौंदर्यशास्त्र के बीच पारस्परिक रुचि ढूँढना। ब्रेन, ब्यूटी एंड आर्ट: एसेज ब्रिंगिंग न्यूरोएस्थेटिक्स इनटू फोकस, 142.

कोसेवा, डी।, और मिरासिएवा, एस। (2018)। मास मीडिया और संस्कृति से लेकर जन समाज तक। बाल्कन सोशल साइंस रिव्यू, 12, 59-71।

जस्टेल, एस।, माइको, जे। एल।, पायने, जी।, और ऑर्डिक्स-रिगो, ई। (2018)। जनहित और मीडिया की वैधता। संगठनात्मक वैधता में (पीपी। 243-254)। स्प्रिंगर, चाम।